बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के मामलों में रेडी रिकॉनर

- शिकायत कौन दे सकता है?
    - कोई भी व्यक्ति, या सिविल सोसायटी का सदस्य, संस्था, या संगठन, सरकारी अधिकारी आदि।
- शिकायत कहां दें?
    - बाल श्रम/बाल बंधुआ मजदूरी क मामले में – चाइल्ड लाइन (1098)/पेंसिल पोर्टल/पुलिस स्टेशन– एसजेपीयू/जिला टास्क फोस/श्रम विभाग/श्रम निरीक्षक, जिला नोडल अधिकारी, सीडब्ल्यूसी, डब्ल्यूसीडी।
    - वयस्क बंधुआ मजदूरी के मामले में – डीएम/एसडीएम/पुलिस/श्रम विभाग।
- क्या जानकारी आवश्यक है?
    - पीड़ित का विवरण, उत्पीड़न का स्थान, रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति '
- बचाव अभियान का हिस्सा कौन हो सकता है?
    - बाल श्रम या बाल बंधुआ मजदूरी के मामले में– डीएनओ, पुलिस/एसजेपीयू, सीडब्ल्यूसी, पीएलवी, डीएम/एसडीएम/तहसीलदार। एनसीएलपी, एनजीओ के साथ–साथ चाइल्डलाइन प्रतिनिधि।
    - वयस्क बंधुआ मजदूर के मामले में – डीएम/एसडीएम/तहसीलदार, श्रम निरीक्षक, पुलिस, गैर सरकारी संगठन
- बचाव सुविधा में:
    - मालिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें; पीड़ितों और मालिकों/अभियुक्तों को अलग करें ताकि वे पीड़ितों को डराएं नहीं।
    - पुलिस सबूत इकट्ठा करेगी
    - डीएम और डीएनओ, पीड़ितों को पुलिस सुरक्षा और संसाधनों की सुविधा प्रदान करना और पीड़ितों और आरोपियों के लिए अलग परिवहन प्रदान करना
- बचाव के पश्चात्:

<u>बाल श्रम या बाल बंधुआ मजदूरी के मामले में:</u>

अ. पीड़ित जे.ज.एक्ट के तहत परिभाषित देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चे की श्रेणी में आते हैं।

ब. सीडब्ल्यूसी के समक्ष बाल पीड़ितों को पेश करें जो तब जांच का आदेश देंगे जिसमें जे.ज.एक्ट की धारा 31 के अनुसार चिकित्सा परीक्षण, उम्र का निर्धारण, मध्यस्थ देखभाल और संरक्षण माता–पिता का पता लगाना या यदि सीडब्ल्यूसी योग्य समझे तो बच्चे को माता–पिता के साथ भेजना, गृह सत्यापन आदि शामिल हो सकता है .

स. बच्चों की पहचान का खुलासा न करें, विशेष रूप से मीडिया को जे.ज.एक्ट की धारा 74 के तहत दिशानिर्देशों का पालन करें।

<u>वयस्क बंधुआ मजदूरी के मामले में:</u>

अ पीड़ितों को केंद्रीय सेक्टर योजना के अनुसार जांच के लिए डीएम/एसडीएम के समक्ष पेश करें।

यदि एफ.आइ.आर. पहले से दर्ज नहीं है, तो एफआईआर दर्ज करने के लिए कौन शिकायत कर सकता है?

अ. पुलिस/एसजेपीयू और पीएलवी सुसंगत कानूनों की पहचान एवं समर्थन कर सकते हैं।

ब. डीएनओ, पुलिस/एसजेपीयू, पीएलवी, श्रम निरीक्षक या कोई भी जो बचाव का हिस्सा था। SLSA/DLSA प्राथमिकी दर्ज करने में सहायता करेगा। यदि कोई शिकायत दर्ज करने को तैयार नहीं है तो प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने के लिए जेजेबी / एसएलएसए को लिख सकता है।

स. बाल श्रम के मामलो में जहां कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है, सीडब्ल्यूसी जेजेबी को भी लिख सकती है कि वह पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दे।

प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सुसंगत धाराएँ।

बीएलएसए धारा 9 (2)	जो कोई भी एक मजदूर से बंधुआ ऋण के लिए कोई भुगतान स्वीकार करता है,	संज्ञेय और जमानतीय	3 साल तक कारावास और जुर्माना
बीएलएसए धारा 16	जो कोई किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी करने के	संज्ञेय और जमानतीय	3 साल तक कारावास और 2,000

	लिए बाध्य करता है,		रुपये तक का जुर्माना।
बीएलएसए धारा 17	जो कोई बंधुआ ऋण अग्रिम करता है	संज्ञेय और जमानतीय	3 साल तक कारावास और 2,000 रुपये तक का जुर्माना।
बीएलएसए धारा 18	जो कोई भी किसी भी प्रथा, परंपरा, अनुबंध या समझौते को लागू करता है जिसमें किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी प्रणाली के तहत काम करने की आवश्यकता होती है,	संज्ञेय और जमानतीय	3 साल तक कारावास और 2,000 रुपये तक का जुर्माना।
बीएलएसए धारा 19	जो कोई भी बंधुआ मजदूर की किसी भी संपत्ति को पुर्नस्थापित करने में विफल रहता है।	संज्ञेय और जमानतीय	1 वर्ष तक कारावास और/या 1,000 रुपये तक का जुर्माना
बीएलएसए धारा 20	अपराध का दुष्प्रेरण	संज्ञेय और जमानतीय	अपराध के समान
जेजे एक्ट धारा 76	बच्चे को भीख मांगने के लिए नियोजित करता है	संज्ञेय और गैर–जमानतीय	5 साल तक कारावास और 1,00,000 रुपये का जुर्माना।
जेजे एक्ट धारा 76	भीख मांगने के लिए बच्चे को विच्छिन्न या अपंग करता है	संज्ञेय और गैर–जमानतीय	7 से 10 वर्ष का कारावास और 5,00,000 रुपये का जुर्माना।
जेजे एक्ट धारा 77	शराब या ड्रग्स देना	संज्ञेय और गैर–जमानतीय	7 साल तक कारावास और 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना।
जेजे एक्ट 78	शराब या ड्रग्स की तस्करी	संज्ञेय और गैर–जमानतीय	7 साल तक कारावास और 1,00,000 रुपये का जुर्माना।
जेजे एक्ट	बंधक में बच्चे को नियोजित	संज्ञेय और गैर–	5 साल तक

धारा 79	करना	जमानतीय	कारावास और 1,00,000 रुपये का जुर्माना।
जेजे एक्ट धारा 81	किसी भी उद्देश्य के लिए बच्चों को बेचना, खरीदना	संज्ञेय और गैर–जमानतीय	5 साल तक कारावास और 1,00,000 रुपये का जुर्माना।
सीएलए धारा 3/14(1)	किसी भी व्यवसाय और प्रक्रिया में बच्चे को नियोजित करना	संज्ञेय और जमानतीय	6 माह से 2 साल तक कारावास या 20,000 रु. का जुर्माना या दोनों
सीएलए धारा 3ए/14(1ए)	किशोरों को निषिद्ध प्रक्रिया या उद्योग में नियोजित करना	संज्ञेय और जमानतीय	6 माह से 2 साल तक कारावास या 20,000 रु. से 50,000 रुपये का जुर्माना या दोनों
सीएलए धारा 3,3ए/14(2)	बाद में समान अपराध	संज्ञेय और जमानतीय	1 वर्ष से 3 वर्ष तक कारावास
सीएलए धारा . 3,3ए/14(2)	बाद में माता–पिता/अभिभावक द्वारा समान अपराध	संज्ञेय और जमानतीय	रु. 10,000 तक जुर्माना
सीएलए धारा 14(3)	अधिनियम के तहत किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन	असंज्ञेय और जमानतीय	1 महीने तक कारावास या 10,000 तक जुर्माना या दोनों

<u>पुनर्वास:</u>

I. <u>बाल और किशोर श्रम या बंधुआ मजदूरी के मामले में</u>

1. <u>निम्नलिखित के लिए श्रम विभाग को लिखें:</u>

अ. **पिछली बकाया मजदूरी के लिए** जिला श्रम आयुक्त/श्रम निरीक्षक या श्रमिकों के विरूद्ध अपराध प्रकोष्ठ से संपर्क करें।

ब. रु. 20,000 प्रति बच्चा नियोक्ता स वसूल किया जावें और बाल श्रम पुनर्वास–सह–कल्याण कोष में जमा किया जावे। यह सुनिश्चित करें कि सरकार ऐसे फण्ड में प्रत्येक बच्चे के लिए 15000 रू. की अतिरिक्त राशि जमा करती है।

स.. सरकार बच्चे के एक वयस्क सदस्य को रोजगार प्रदान करूंगी या प्रतिबच्चा 5000 रुपये का योगदान देगी।

द. सुनिश्चित करें कि मूल राशि और ब्याज के साथ ब्याज का हस्तांतरण फंड से बच्चे के बैंक खाते में अंतरित किया जावे जब ऐसा बच्चा या किशोर 18 वर्ष की आयु प्राप्त करता है।

इ. सुनिश्चित करें कि श्रम विभाग प्रत्येक बच्चे और किशोर के लिए एक बैंक खाता खुलवाये।

2. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कार्यक्रम को उनके एनसीएलपी कार्यक्रम में बच्चे के नामांकन के लिए लिखें।

3. कौशल विकास कार्यक्रम ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (DDU-GKY) आदि में किशोरों के नामांकन के लिए ग्रामीण विकास विभाग को लिखें।

4. निम्नलिखित के लिए शिक्षा विभाग को लिखें:

अ. विद्यालय में 6–14 वर्ष के बच्चों का नाम दर्ज कराना।

ब. केजीबीवी (एससी/एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, बीपीएल–जनरल इन ब्लॉक लेवल) में बालिकाओं का नाम दर्ज कराना।

स. आवासीय विद्यालयों में अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों का नाम दर्ज कराना (जिला + 2 और ब्लॉक स्तर कक्षा V–Xii)

द. कक्षा प्रथम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और कक्षा से अल्पसंख्यक बच्चों के लिए वजीफा।

II वयस्क बंधुआ मजदूरी के मामलों में

1. जिला मजिस्ट्रेट मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार रिहाई प्रमाण पत्र जारी करता है। और बंधुआ मजदूर पुनर्वास के लिए केंद्रीय सेक्टर योजना के अनुसार बंधुआ मजदूर पुनर्वास कोष से तत्काल नकद सहायता की राशि जारी करता है।

2. मनरेगा योजना के तहत जॉब कार्ड और 100 दिनों के रोजगार के लिए पंचायत या ब्लॉक परियोजना अधिकारी को लिखें। मनरेगा जॉब कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को संबंधित राज्य की वेबसाइट से मनरेगा के तहत जॉब कार्ड के लिए प्रोफार्मा डाउनलोड करना होगा और विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र ग्राम कार्यालय या उनके स्थानीय क्षेत्र क किसी अन्य समकक्ष कार्यालय में जमा करना होगा। वैकल्पिक रूप से, वे स्थानीय पंचायत से मनरेगा जॉब कार्ड फॉर्म भी प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आवेदन निम्नलिखित विवरण उल्लेखित करके सादे कागज पर किया जा सकता है:

- आवेदक का फोटाग्राफ
- नाम, आयु और लिंग
- गांव का नाम
- ग्राम पंचायत का नाम
- ब्लॉक का नाम
- आवेदक (आवेदकों) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आईएवाई/एलआर के लाभार्थी हैं या नहीं, इसका विवरण
- आवेदकों के नमूना हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

एक बार आवेदक द्वारा आवेदन पत्र जमा करने के बाद, ग्राम पंचायत निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर फॉर्म का सत्यापन करती हः

- आवेदन करने वाले आवेदक वयस्क होने चाहिए।
- सभी आवेदकों के पास स्थानीय मूल निवासी होना चाहिए।
- यदि कोई महिला अविवाहित है और अकेली रह रही है तो वह भी मनरेगा योजना के तहत आवेदन कर सकती है।

आवेदन के सफल सत्यापन के बाद, आवेदकों को जॉब कार्ड जारी किया जाता है। यदि परिवार के एक से अधिक सदस्यों ने नरेगा के तहत आवेदन किया है, तो रोजगार योजना के लिए आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर प्रत्येक सदस्य को जॉब कार्ड जारी किया जावेगा।

3. निम्नलिखित के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को लिखें:

अ. कम से कम 3 महीने के लिए बचाए गए /पीड़ित परिवारों को आवश्यक वस्तुओं (पीडीएस) की आपूर्ति – सर्कल अधिकारी को लिखें

ब. राशन कार्ड तत्काल जारी करना सुनिश्चित करें

प्रक्रिया:– राशन कार्ड प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी पोर्टल (http://mpedistrict-gov-in/Public/index-aspx) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए और नए बीपीएल राशन कार्ड प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म डाउनलोड करके विधिवत आवेदन करना चाहिए, भरे हुए फॉर्म को जन सेवा केंद्र के अधिकारियों को जमा करना होगा। जमा करने पर, आवेदक को आपके आवेदन की प्राप्ति की पुष्टि करने वाली एक पावती संख्या प्राप्त होगी। संबंधित प्राधिकारी अनुमोदन के 30 कार्य दिवसों के भीतर राशन कार्ड जारी करेगा।

4. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 और नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 के अंतर्गत पुनर्वास में सहायता के लिए एक पैरा लीगल वालटियर और पीड़ितों का न्यायलय में प्रतिनिधित्व करने के लिए एक पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति करेगा।

5. पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के तहत आजीविका लाभ के लिए ग्रामीण विकास विभाग, एसआरएलएम के जिला अधिकारी को लिखें।

6. महिला एवं बाल विकास विभाग को पत्र लिखकर सुनिश्चित करें कि महिला शक्ति केंद्र योजना के तहत पीड़ित महिलाओं को हक और राहत मिल सके।

7. प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत भूमि आवंटन के लिए पंचायत और तहसीलदार को लिखें – लाभार्थी वे लोग हैं जिनके नाम एसईसीसी 2011 में सूचीबद्ध हैं या बीओसीडब्ल्यू में नामांकित हैं।

एक नागरिक प्रधानमंत्री आवास योजना (यू) के अंतर्गत लांभावित हो सकता है, यदि वह **ई डब्लू.एस. एल.आई.जी.** या **एम.आई.जी.** श्रेणी में निम्न विवरण में आता हैः–			
श्रेणी	वार्षिक हाउसहोल्ड आय (रू.लाख में)	घर का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	वर्टिकल हेतु पात्र
ई.डब्लू.एस आर्थिक कमजोर वर्ग	03 लाख तक	30 वर्ग मीटर	ए.एच.पी., बी.एल.सी, सीएलएसएस एवं आईएसएसआर
एल.आई.जी. लोवर इनकम ग्रुप	03–06	60 वर्ग मीटर	सीएलएसएस
एम.आई.जी.–1 मीडिल इनकम ग्रुप–1	06–12	160 वर्ग मीटर	सीएलएसएस
एम.आई.जी.–2 मीडिल इनकम ग्रुप–2	12–18	200 वर्ग मीटर	सीएलएसएस

विचारण के दौरान पीड़ित (पीड़ितों) को कानूनी सहायता प्रदान करना

1. पीड़ित को हस्ताक्षर करने के पूर्व वकालतनामा के महत्व तथा अर्थ के बारे में बताएं। कानूनी कार्यवाही को स्पष्ट करें।

2. यदि धमकी या उत्पीड़न की आशंका है, तो उस क्षेत्राधिकार (क्षेत्राधिकारों) की स्थानीय पुलिस को एक पत्र लिखें जहां पीड़ित रहते हैं और उत्पीड़न से सुरक्षा की मांग करते हैं। पत्र के साथ रिहाई प्रमाण पत्र, शिकायत और प्राथमिकी की एक प्रति संलग्न करें।

3. सुनिश्चित करें कि जांच अधिकारी कानून द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर एक सटीक आरोप पत्र दाखिल करें।

----------000----------